Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 1st August, 1984."

MR DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That this House do agree with the Seventy-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 1st August, 1984."

The Motion was adopted.

———

15.02 hrs,

RESOLUTION *RE*: DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

MR. DEPUTY-SPEKER : The House will now take up further discussion of the following resolution moved by Shri Ram Lal Rahi on 27th April, 1984 :

"That House is of the opinion that Government have failed to ameliorate the lot of low income group peopie through planned development of rural areas on account of serious inadequacies in the administrative machinery and therefore, recommends to the Government to devise pragmatic policies by laying emphasis on education and moral values and by revamping the administrative structure so as to ensure integrated development of the rural areas for upliftment of the masses."

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मान्यवर, मेरा रिजोल्यूशन जो है वह 27 अप्रैल को सदन में पेश किया गया था और उसके बाद ही मैं एक शब्द कह पाया था उसके बाद समय समाप्त हो गया था, इसलिये आगे चर्चा नहीं हो पायी थी। मैंने कहा था कि मैं गांव का निवासी रहा हूं। शहरी सीमा में प्रवेश करने के बाद मेरा ग्रामीण जीवन से अभी भी लगाव है और उसकी जो समस्यायें हैं. गांवों के रहने वालों की जो समस्यायें हैं, जिस अपेक्षा और अभाव के जीवन में गांव के लोग रह रहे है, कैसे अंधियारे में गांव बस रहे हैं उनसे मैं भली भांति परिचित हूं।

और मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि लगभग 36 साल देश को आजाद हुए हो गये, 37वां चल रहा हैं और छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर है, सातवीं योजना का भो प्रारूप मोटे तौर पर हम लोगों को दिखा दिया गया हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि गांव के रहने वालों की हालत बावजूद छठी योजना बीत जाने के, बावजूद इसके कि गांव के नाम पर ग्रामवासियों के नाम पर, उनके विकास के नाम पर, गांव के गरीब लोगों के अल्प जोतकार या खेतिहर मजदूर लोगों की प्रगति के नाम पर न मालूम कितना धन खर्च किया गया... लेकिन निरन्तर गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी और भुखमरी बढ़ती गई है। मैं योजनाओं के कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा, जिन से आप देखेंगे कि क्या हालत हो रही है ?

मैं संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इन पर जरा ध्यान दें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 53 लाख बेरोजगार थे, दूसरी योजना के अंत में यह संख्या 71 लाख हो गई और तृतीय योजना के अन्त में तो यह बढ़कर दुगनी संख्या लगभग 126 लाख हो गई।

अब मैं 1980 के बाद के आंकड़े बताता हूं जिनसे पता लगेगा कि बेरोजगारी बढ़ने

[श्री रामलाल राही]

का क्रम किस प्रकार रहा है। 1980 में 162 लाख बेरोजगार थे, 1981 में 178 लाख हो गये, 1982-83 में 197 लाख 53 हजार हो गये और 1983-84 में 219 लाख के लगभग यह संख्या पहुंच गई है।

यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी मिटाने के नाम पर धन तो खर्च किया गया, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ, उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिला बल्कि बड़े लोगों को मिला है।

मंत्री महोदय को देखना चाहिये कि गांव की आवश्यकताएं क्या हैं, गांव का रहन-सहन कैसा है। गांव के 37 साल की प्रगति के आंकड़ों के बावजूद जो वहां अभाव की स्थिति है, उसको देखते हुए क्या आपने इस बात का अध्ययन करने का प्रयास किया कि आखिर इतना धन इन योजनाओं में लगाने के बावजूद गांव आज उपेक्षित से क्यों लग रहे हैं, लोगों में निराशा क्यों है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? आपको इस दिशा में अध्ययन कराना चाहिये था।

मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इस देश के लोगों की मेहनत का पैसा जो सरकार के खजाने में आता है, उसे खर्च करने का हिसाब-किताब, बही-खाता तो सरकार की कुर्सी पर बैठने वालों ने बना दिया, लेकिन उसके परिणाम क्या निकले, इस पर कहीं नजर नहीं डाली गई। मेरा साफ कहना है कि अगर एक बार भी कहीं नजर डाली गई होती तो शायद आज जो आंकड़े मैंने पढ़कर सुनाये हैं, यह आपको सुनने को न मिलते। पहली पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों में बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी के बजाय गिरावट आनी चाहिए थी।

आप कह सकते हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ती गई है इस कारण बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। इसी सप्ताह एक प्रश्न के जवाब में, संभवत: मंत्री का जवाब था, वह मेरे पास इस समय है नहीं, मैंने कार्यवाही पढ़ी थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ी है तो उन्होंने इससे इंकार किया और कहा कि ऐसा नहीं है। सरकार यह तर्क नहीं दे सकती कि जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि कैबिनेट के एक मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में इस बात से इंकार किया है।

37 सालों की आजादी के दौरान सरकार ने गांवों के लोगों की मूल आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मंत्री महोदय भली भांति जानते हैं कि गांव और शहर की परिभाषा क्या है। शहर की परिभाषा यह है कि वहां पर 25 प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर आश्रित न हों और गांव की परिभाषा यह है कि वहां पर 75 फीसदी से अधिक लोग केवल खेती पर अपना जीवन-यापन करते हों।

हमारे देश में तो 80 फीसदी लोग कृषि पर जीवन बिता रहे हैं। केवल 20 फीसदी लोग दूसरे रोजगार और धंधों में लगे हैं और उनका शहरी जीवन है। हो सकता है कि हमारे पक्ष और उस पक्ष में बैठने वाले कुछ ऐसे भी लोग हों, जिनका दोहरा जीवन है एक शहरी जीवन और और दूसरा देहाती जीवन। जब हम लोग शहरी जीवन की चकाचौंध में पड़ जाते हैं, तो हम गांवों के लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को भूल जाते है, उनके जीवन में सुधार लाने की जरूरत से विमुख हो जाते हैं। हमने यह बात देखी है और इस लिये हम इस

निष्कर्ष पर पहुंचे है कि 37 सालों की आजादी में सरकार का यह फेल्युर रहा है कि हमारे गांव उपेक्षित रहे हैं। आज सरकार को उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह सही है कि गांवों के विकास के लिए सरकार ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। गांव से लेकर जिले तक एक बड़ी लंबी प्रशासनिक मशीनरी बनी हुई है। जिला अधिकारी के नीचे तहसील अधिकारी, उसके नीचे विकास खंड, उसके नीचे पचायत अफसर और न्याय पंचायत और उसके बाद गांव सभा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिन गांव सभा को प्राथमिक इकाई बनाया है, क्या उसने यह देखने का प्रयास किया है कि क्या गांव सभा वास्तव में गांव के विकास और उन्नयन और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है, क्या सरकार ने उसको पर्याप्त साधन और अधिकार दिए हैं, ताकि वह गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

मेरा कहना है कि इस सरकार को लोकतंत्र दो ही जगह दिखाई पड़ा : एक तो लोकतंत्र की सुप्रीम इकाई, यह लोक सभा और प्रदेशों में विधान सभाएं। लोक सभा और विधान सभाएं बनी रहें, लोक सभा और विधान सभा में लोग चुन कर आ जाएं, लोक सभा और विधान के लोगों को सुख-सुविधाएं मिलें, भले ही नीचे की इकाई मजबूत रहे या न रहे, इसी में इस सरकार को दुनिया का सबसे अच्छा और निखरा हुआ लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। मैं लोहिया वादी नहीं रहा हूं मैं सोशलिस्ट पार्टी में भी नहीं रहा हूं। चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो, अगर उसकी नीति और नीयत सही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए।

मुझे तो डा० लोहिया की सब बातों में से, उस सम्मानित व्यक्ति की सब बातों में से एक ही बात पसंद आई। जिसमें उन्होंने चौखंडा राज्य की कल्पना की थी। इस देश में कैसी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। केन्द्र कैसा हो, देश की राजधानी कैसी हो, देश की सर्वोच्च इकाई लोकसभा कैसी हो, विधान सभा कैसी हो, उसके अधिकार क्या हों, इन सब को बताया था। जिला परिषद कैसी हो, उसको क्या अधिकार हों। फिर उससे नीचे उतर कर सबसे प्राथमिक इकाई जिसे गांव सभा कहते हैं, उसे क्या अधिकार हो। इन सब की व्याख्या उसने की थी। उसने बताया था कि इस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। जब प्राथमिक इकाई मजबूत होगी तभी लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा। जब हम उसे साधिकार बनाएंगे तभी गांव के आदमी के जीवन को सुधारने में सफल हो सकेंगे।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सत्ता में बैठने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो जहां गांव सभा बनाई थी यदि उसको वे साधिकार बनाते। ग्राम प्रधान को, गांव के छोटे कर्मचारी, जिसे कहते हैं लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, जिसे कहते है वी० एल० डब्ल्यू, हैल्थ वर्कर, अमीन, कृषि अमीन, पतरौल, उसके बाद पुलिस का सिपाही, दरोगा, ब्लाक के अधिकारी, बी० डी० ओ० और जिले के अधिकारी, इन सब का बस्ता उठाने वाला वह शख्स न रहता।

सम्मानित सेठी जी बैठे हैं। अब दूसरा विभाग इनके सुपुर्द किया गया है। ये अच्छी

[श्री रामलाल राही]

तरह से जानते हैं कि गांव प्रधान की क्या हैसियत रही है। गांव परिषद् के क्या अधिकार हैं। गांव परिषद को आपने मजबूत नहीं किया। गांव कैसे मजबूत होगा। आप ने जो योजनाएं बनाई हैं, जिनके नाम पर आप हर महीने इतने कागज खराब करते हैं, उसमें झूठे आंकड़े आप लिखते हैं। ये सरकारी किताबें हैं, कभी-कभी सच भी बतलाती है। आम तौर पर हमने देखा है कि झूठे आंकड़े आपकी तरफ से दिए जाते रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के लोग बहुत दुखी हैं। जहां एक तरफ शहरों में देखते हैं कि रात में भी दिन दिखाई देता है, चमचमाती रोशनी में वहीं गांवों की यह हालत है कि वहां हमें दिन में भी अंधकार दिखाई देता है। इस अंधियारे को अभी हम बदल नहीं पाए हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि इसमें आप सुधार लाएं। अगर आप चाहते हैं कि शोषण, शोसित और शोषक की परिभाषा में परिवर्तन हो। इसके रास्ते में बदलाव आए तो आपको गांव और शहर के इस फर्क को दूर करने के लिए गांव की तरफ मुड़ना होगा। हमने कई बार अखबारों में प्रादेशिक सरकारों के मुख्य मंत्रियों को भाषणों को पढ़ा है, जिनमें कहा गया है कि हम शहर से गांव की ओर जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं वे कहां तक चल पाए हैं। गांव तक पहुंच पाए या गांव के नजदीक से होकर ही चले गए। गांव के किसी गलियारे में, किसी कच्चे रास्ते पर गए या नहीं। मेरा साफ जानना है कि जिन मुख्य मंत्रियों या जिन केन्द्रीय नेताओं ने कहा है, उन्होंने गलत कहा है। वे लोग नगर से पक्की चलने वाली सड़क तक ही जाते हैं, गांव के किनारे तक जाते हैं, लेकिन गांव के गलियारे तक नहीं गए हैं। अगर गए भी हैं तो गांव तक गए हैं, जिस गांव में वह खुद रहते हैं या गांव तक जाने के लिए उनको पक्की सड़क चाहिए। इसके अलावा जो गांव पहाड़ियों पर बसते हैं, जो देश का पिछड़ा इलाका है, जो देश का पहाड़ी इलाका है देश की नदियों के कच्छारों में बसने वाले लोगों तक उनकी निगाह नहीं गई है। जिन गांवों में 80 फीसदी लोग बेकार है, बीमार है और बेरोजगार हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन तक आपकी नजर नहीं जाती है। जिनके शोषण के लिए चन्द लोग, बड़े भूस्वामी लोग गांव से चले हैं और शहर में जाकर बड़े-बड़े पक्के महल बना लिए हैं। इसके अलावा कोई परिवर्तन अभी तक ग्रामीण जीवन में नहीं आ पाया है। मेरा साफ जानना है कि गांवों में अभी भी 90 फीसदी से अधिक लोग बेबसी का जीवन बिता रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जो बेरोजगारी के हैं। आपने जो प्रगति की है और प्रगति के आंकड़े जो आपने बताए हैं, उनके संबंध में मैं आपसे जानना चाहूंगा। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। जब तक कृषि और उस पर आधारित कामों के लिए सुधार का दृष्टिकोण सरकार नहीं अपनाती तब तक गांव के लोगों के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। गांव के लोग अभाव का जीवन बिताते ही रहेंगे। कृषि का उद्धार तभी होगा, जब खेती की पैदावार बढ़े और और खेती की पैदावार तभी बढ़ सकती हैं जब आप रसायनिक खाद दें। रसायनिक खाद से ही पैदावार नहीं बढ़ सकती है, जब तक कि आप खेतों में पानी न दें। आपकी नई-नई किस्में आ रही हैं, चाहे गेहूं की हों, चाहे धान की हों, चाहे

दालों की हों, आप तब तक पैदा वार को नहीं बढ़ा सकते हैं, जब तक कि आप खेती के लिए पहली प्राथमिकता पानी उचित मात्रा में न दें। आपने 37 सालों में सिंचाई की जो उपलब्धि की है—वह क्या है? उत्तर प्रदेश में अभी तक 44 प्रतिशत में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध करा पाये हैं, जिनमें निजी साधन भी शामिल हैं। असम में 17 प्रतिशत, बिहार में 33 प्रतिशत, गुजरात में 19 प्रतिशत, केरल में 12 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 12 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 11 प्रतिशत तथा इसी प्रकार से दूसरे छोटे-छोटे प्रदेशों में कहीं पर 4 5 या 7 प्रतिशत हैं। आप बतलाइये—आप कहते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़े तो यह कैसे बढ़ेगा? जब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, गांव की खेती में अन्न पैदा नहीं होगा, इतना अन्न पैदा नहीं होगा कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तब तक यह देश तरक्की नही कर सकता। आप कहते हैं कि अन्न के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गये हैं, परन्तु वास्तविक परिस्थिति यह है कि आज भी आप विदेशों से अन्न मंगा रहे हैं।

कल मैंने गन्ने के संबंध में, उसमें लगने वाले कीड़े के बारे में, नियम 377 के अधीन इस सदन में चर्चा की थी। मैं स्वयं देखकर आया हूं और मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से आप विदेशों से गेहूं मंगा रहे हैं, एक दिन वह आ जाय जब गन्ने का उत्पादन इतना गिर जायेगा कि आपको चीनी निर्यात करने की बजाय आयात करनी पड़ेगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं—अगर आप चाहते हैं कि गांव सुखी हों, गांव समृद्ध हों तो गांवों में खेती के उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिये। लेकिन यह कैसे होगा? सिंचाई के साधन बढ़ाइये, भूमिसुधार कीजिये। बंजर भूमि को तोड़ा जाना चाहिये। अभी भी बहुत बंजर भूमि हमारे देश में पड़ी हुई है उसको कृषि योग्य बनाइये। हजारों हैक्टेअर भूमि हमारे देश में पड़ी हुई है। हरदोई जनपद में हजारों एकड़ भूमि ऊसर पड़ी हुई है। उसके सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आप हरदोई को छोड़ दीजिये, उन्नाव को ले लीजिए या रायबरेली जिले को लीजिये जहां से हमारी प्रधान मंत्री जी कई बार चुन कर आ चुकी हैं। वहां भी ऊसर जमीन बहुत बड़ी तादाद में है उसको सुधारने के बारे में हम नहीं जानते कि आपके आंकड़े क्या बतलाते हैं। लेकिन मैं तो वह बात कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जितनी ऊसर जमीन आपके देश में है, पिछले 37 सालों में उसका 10 प्रतिशत भी ऐसा नहीं बना सके हैं जिसमें अन्न पैदा किया जा सके। वह खेती करने लायक हो सके। खेती करना तो दूर रहा, ऐसा भी बना पाये है कि बजाय खेती के बागवानी ही हो सके। पेड़-पौधे उसमें लगाये जा सकें इसलिये आज जरूरत है कि ऊसर भूमि को सुधारा जाय।

इस देश में भूमि कटाव हो रहा है। इस देश में नदियों की बहुतायत है। हर प्रदेश के हर क्षेत्र में छोटी-बड़ी नदियां हैं। कहीं 6-6 महीने में बारिश होती है, कहीं चार-चार महीने में बारिश होती है, जहां-जहां देश में ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश नहीं होती है, जैसे राजस्थान है, उसमें सुनने को मिलता है कि बारिश हो गई और उससे इतने गांव इतने गांव डूब गये। ऐसा क्यों होता है? अगर देखा जाय तो 6 योजनायें बीत गई लेकिन इस दिशा में कोई काम

[श्री रामलाल राही]

नहीं हुआ । इन छः योजनाओं के आंकड़े मेरे पास थे लेकिन अभी वे मुझे मिल नहीं रहे हैं । अगर आप उन आंकड़ो को देखते, तो अपने आप स्पष्ट हो जाता कि आज तक के परिणाम क्या रहे हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : How much more time do you require, Mr. Rahi ? You have already taken half an hour.

श्री राम लाल राही : मुझे कम से कम एक घंटा और दीजिए और साढ़े चार बजे तक मुझे बोलने दीजिए क्योंकि यह मेरा पहला संकल्प है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must conclude by 4 O' Clock, and this is as a special case because you have prepared so much, you have done so much of home work.

श्री राम लाल राही : मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के उपाय नहीं किये जाते, भूमि-सुधारों के उपाय नहीं किये जाते, कटाव को रोकने के उपाय नहीं किये जाते और जब ऐसी बात है, तो कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा । वह गिरता ही रहेगा ।

आज बाढ़ क्यों आ रही है । अभी बाढ़ पर चर्चा हो रही थी । इस सदन में मैं कई बार पहले कह चुका हूं इस बाढ़ के बारे में लेकिन इस सरकार के न तो कान खुले हैं हैं और न इस सरकार के प्रशासन तंत्र के ही कान खुले हैं । दोनों के कान बंद हैं और आखें भी बंद हैं । इस सदन में बाढ़ को रोकने के लिए और कृषि के क्षेत्र को बचाने के लिए क्या सुझाव दिये जा रहे हैं और बाढ़ें क्यों आ रही हैं और जो कारण बतलाए जा रहे हैं, क्या वे कारण सही हैं । अगर वे सही हैं, तो उन पर अमल होना चाहिए । सरकार इस दिशा में कुछ सुनने को तैयार नहीं है । आज जितनी बारिश हो हो रही है, उतनी बारिश छठी पंचवर्षीय योजना में भी हुई और पहले भी हुई । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी उतनी बारिश हुई और उससे पहले भी हुई । आजादी से पहले भी ऐसा ही था बारिश होती थी । लेकिन बाढ़ से इतना नुकसान नहीं होता था । क्या इस बात का अध्ययन करने की कोशिश की गई कि आखिर आज हजारों के हजारों गांव बाढ़ से क्यों बह जाते हैं ? क्या इस बात का अध्ययन किया कि हजारो लाखों हैक्टर कृषि भूमि जिसमें धान, ज्वार और मक्का की फसलें पक कर खड़ी होती हैं और सितम्बर के महीने में बाढ़ आ जाती है फसलें बहा ले जाती है तो गांव का किसान क्यों दाने-दाने को मोहताज हो जाता है ? अगर, अध्ययन किया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ? नदियों का जमीन का कटाव होते होते पटाव हो गया है और धरातल ऊंचा हो गया है । इससे पानी का फैलाव बढ़ गया है । जहां नदी बाढ़ आने पर उसके एक किलोमीटर किनारे के अन्दर बारिश होने पर गांव डूबते थे, वहीं फैलाव अधिक होने से पांच-पांच और दस-दस किलोमीटर नदियों के किनारे के अंदर आने वाले गांव डूब जाते हैं । उनकी खड़ी की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है । अगर, बाढ़ को रोकना है, किसान की मदद करनी है, उनकी फसलों को बचाना है तो आपको छोटी-बड़ी सभी नदियों को गहरा करना पड़ेगा । इस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है । लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच और आसाम तक अनेकों जिले बहते जा रहे हैं । दूसरी तरफ सूखे की खबरें

आ रही हैं कि अमुक-अमुक क्षेत्रों में सूखा है, पानी नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, सन् अट्ठारह सौ में कोई सन् था ठीक याद नहीं पड़ता जब एक आयोग बना था। उस आयोग ने सिफारिश की थी कि इस देश की छोटी-बड़ी नदियों को जोड़ने के काम किए जाने चाहिए। अगर, देश को बाढ़ और सूखे से बचाना है तो आपको इस दिशा में पहले काम करना पड़ेगा। बारिश पड़ने पर जो छोटे-छोटे नाले भर जाते हैं, उन नालों को गहरा कराना होगा ताकि उनमें पानी समेटने की क्षमता बढ़े। इससे दोहरे लाभ होंगे। गांव के विकास के लिए आप, मत्स्य पालन और न जाने कितनी बातें किया करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे मैदानी इलाकों में नदी का फैलाव एक-डेढ़ किलो-मीटर तक होता है। लेकिन सितम्बर के बाद आप जायेंगे तो पाखाना के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। कई मील तक आपको जाना पड़ेगा। अगर वहां का किसान चाहे कि उसके खेत को पानी मिल जाए तो नदी के किनारे के खेत को भी एक बूंद पानी मुहैया नहीं होता। अगर, नदी को गहरा करा दें तो सिंचाई और मत्स्य पालन का काम हो सकता है। मत्स्य पालन और देवी आपदाओं के नाम पर आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन यह करोड़ों रुपया आप कितने वर्षों में खर्च कर रहे हैं, अब तक कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, आप अनुमान लगाइये कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छटी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जितना पैसा इन दैवी आपदाओं और खासकर बाढ़ की रोकथाम पर खर्च किया गया, यदि इसी पैसे को कंवर्ट करके यदि यह सरकार वास्तव में लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाना चाहती, यदि इस सरकार में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होती, इस समस्या के स्थाई निदान पर उसी धन को लगाया जा सकता था और यह समस्या हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गई होती। फिर आज हम यहां जो बहस कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता न पड़ती। फिर हम ये आंकड़े यहां नहीं देते कि इतनी जमीन बही, इतना पशु धन का नुकसान हुआ, इतनी फसल मारी गई, आदि आदि। मेरी राय है कि आप बाढ़ की रोकथाम का कोई स्थायी उपाय ढूंडिये। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात आप छोड़िये। यदि कहीं बाढ़ आ गई तो आपने 100 क्विंटल गेहूं दे दिया, किसी दूसरी जगह बाढ़ आ गई तो मुट्ठी भर चना दे दिया, किसी तीसरी जगह बाढ़ आ गई तो आप पूरियों के पैकेट बांट रहे हैं, कहीं कम्बल बांटे जा रहे हैं, कहीं धोतियां बांटी जा रही हैं। इस बंटवारे के माने क्या हैं? इस देश के लोगों को आप टुकड़खोर बनाए रखना चाहते हैं, भिखमंगे बनाए रखना चाहते हैं। इस देश में आप ऐसी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं कि इस देश के नागरिक सरकार के सामने हाथ फैलाने वाले बने रहें और सत्ता में बैठे लोग उनके सामने इस तरह से टुकड़े फेंकते रहें तो वे आपकी जय बोलें। आप जय बुलवाने की इस चीप पोपुलरिटी को, सस्ती लोकप्रियता को बदलिये। जब तक सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं आता, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस देश के ग्रामीण दुखी जीवन को सुखमय जीवन में नहीं बदला जा सकता। यदि सरकार की नियत है कि हम ग्रामीण दुखी जीवन को सुखमय जीवन में बदल दें तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना होगा कि कृषि का विकास किया जाय, भूमि सुधार हो और दूसरे नम्बर पर आपको देवी आपदाओं को रोकना तथा बाढ़ और सूखे का स्थायी निदान निकालना होगा। जब

[श्री रामलाल राही]

तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी गांवों में खुशहाली नहीं आ सकती ।

आप देखिए, आज गांवों में आपने क्या दे रखा है, शिक्षा कैसी है ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने शिक्षा वहां कैसी बना रखी है ? मैं यहां इनकी किताब में से ही कुछ उद्धरण रखना चाहता हूं जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निकाली गई है और संकलित तथा सम्पादित गवेषणा और संदर्भ प्रभाग द्वारा 1983 में की गई है, उसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस देश में 1950-51 में दो लाख 31 हजार प्राइमरी स्कूल थे जो कि 1976-77 में बढ़ कर 6 लाख 51 हजार हो गए । इसी तरीके से छात्रों की संख्या पहले दो करोड़ हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ 97 लाख हो गई है । इन सब आंकड़ों में इन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे यहां प्राइमरी स्कूल काफी संख्या में खुले हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने नये प्राइमरी स्कूल तो खोले, लेकिन क्या कभी इस बात का भी पता लगाया कि इन प्राइमरी स्कूलों में मास्टर जाता है, क्या उनमें मास्टरों के बैठने के लिए कुर्सी हैं, क्या स्कूल भवन भी बना है या खाली स्कूल खोल दिए गए हैं, सिर्फ नाम के स्कूल हैं । श्रीमान, मैं साफ कहना चाहता हूं, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मेरे जनपद सीतापुर में शक्करपुर जिसनी नाम का गांव है, जहा 1947 से भी पहले का स्कूल कायम है, मगर उसकी इमारत आज तक नहीं बनी है । यदि 1947 से पहले बने स्कूल की इमारत आज तक न बनी हो तो 1983-84 में आपने जितने स्कूल बनाये, उनका क्या कहना है । क्या एक भी स्कूल में, 1983-84 में जितने आपने स्कूल गांवों में खोले हैं उनमें एक में भी आप इमारत दे पाये हैं ? नही दे पाये हैं । मैं जानता हू क्योंकि में गांवों में घूमता हूं, खेत की मेड़ मेड़ घूमता हूं, मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है कि इनके स्कूल तो खुले हैं, पर फर्जी हैं । कहीं इमारत है तो मास्टर नहीं जाता, मास्टर है तो इमारत नहीं है, लड़के है तो मास्टर और इमारत दोनों नहीं हैं । गांव के बच्चे जिस बाग में, खलिहान में स्कूल लगता है वहां पहुंच कर अपने घर लौट आते हैं । और आप बता रहे हैं कि बड़ी तरक्की की है । मैं पूछना चाहता हूं किसी गांव में आपने स्कूल खोल दिया और स्कूल की इमारत नहीं है तो वहां बरसात में लड़के पढ़ने जा सकते हैं । क्या गर्मी में चैत और बैसाख में जब लू चलती है और स्कूल की इमारत नहीं है मास्टर जा कर पढ़ा सकता है या बच्चे पढ़ने आ सकते हैं ? क्या बच्चों को मार डालने के लिए कोई बाप अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार होगा ? आपने शिक्षा के नाम पर स्कूल तो कागज पर खोल दिये हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है । जमीन पर 70 फीसदी स्थानों पर आपकी इमारत अभी इस लायक नहीं है जिसमें सारे बच्चे बैठ सकें । 50 फीसदी स्कूल अधूरे पड़े हैं । ही सकता है 30 फीसदी स्कूल जितने आप ने खोले हैं उसमें 30 फीसदी स्कूलों के पास अपनी इमारतें हों । अन्यथा इमारतें नही हैं। एक तो यह शिक्षा, दूसरी और शहरी चकाचौंध वाली कनवेंट और सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई । दूसरी ओर गढैया के स्कूल की पढ़ाई क्या यह बात साबित नहीं करती है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यहां शोषक और शोषित का रिश्ता मजबूत बना हुआ है ?

श्री मूल चन्द डागा : ऐसा नहीं है ।

श्री मनी राम बागड़ी : पढ़ने वाले बच्चे

स्कूल की छत गिरने से दब कर मर गए, क्या यह आपको मालूम है ? उस पर कोई आपको शर्म है कि नहीं ?

श्री राम लाल राही : मै इंकार नहीं करता, इन्होंने किया है। लेकिन उसके परिणाम कुछ नहीं निकले। जितना खर्च किया है उसका चौथाई भी अच्छा परिणाम निकलता तो मैं नहीं कहता कि आपको शिक्षा नीति में परिवर्तन करना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि जब तक दोहरी नीति शिक्षा ही रहेगी, शोषण और शोषित का रिश्ता बना रहेगा, गरीबी और अमीरी की खाई बनी रहेगी आप ऊंच नीच के भेद को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आपको शिक्षा की नीति में भी परिवर्तन करना चाहिए। गांव के लोगों के बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए जिस तरह दिल्ली में आपके बच्चों को मिलती है। जिस तरह बड़े-बड़े नगरों के रहने वाले बड़े अफसरों के बच्चों को मिलती है, वही शिक्षा गांव के बच्चों को भी मिले।

आप कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। डींग हांकते हैं। हम नहीं कहते कि कभी लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि देश के नागरिकों में फर्क डालकर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो। अगर आप की नीति में ऐसा है तो वह नीति गलत है। अगर आपकी नीयत में है तो आपकी नीयत की गलती रही है। इस नीयत और नीति को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। गांव के विकास और तरक्की का दूसरा मुख्य साधन कृषि पर आधारित पशु-पालन है। मेरी मान्यता है कि अगर आप पहली पंच-वर्षीय योजना से ही गांव के इन बेरोजगार, खेतीहर मजदूरों को, जिनको आप खेती नहीं दे सकते, ऐसे रोजगार जो कल-कारखानों के कायम होने से मिलते हैं, नहीं दे सकते थे तो इनको कम-से-कम दो दुधारू पशु, जो 5, 7, 10 किलो दूध देते हों, ऐसे जानवर तो इनके दरवाजे पर बंधवा सकते थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गांव के विकास और खेतिहर मजदूरों और बेरोजगारों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या आपने पशु-पालन की दिशा में कोई ठोस कदम उठाये ?

आप जानते हैं कि जो देशी पशु होते हैं वह कैसे होते हैं। कहीं-कहीं 10-15 गाय हैं लेकिन उन 15 गायों का दूध कुल 5 किलो होता है। क्या इसको बदलकर आपने एक गाय मे 15 किलो दूध पैदा करने की स्थिति लाने की कोशिश की ? मेरा साफ कहना है कि आपने गांव के लोगों की जिन्दगी को सुधारने का जो दूसरा हथियार पशु-पालन का था, उसको करने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप की 7 वीं योजना प्रारंभ होने को है, छठी योजना खत्म हो रही है, इसमें आपको इस देश के पशुओं की नस्ल सुधारने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे आधा किलो दूध देने वाले पशुओं का जीवन बदले और उनके स्थान पर 10,15 किलो दूध देने वाले पशु किसान के दरवाजे पर बधे। अगर आप यह कर सकेंगे तो जहां ये लोग दूध बेचकर आर्थिक दृष्टि से कुछ पैसा कमा सकेंगे, वहां इनके बच्चे दूध पीकर स्वस्थ और सुखी होंगे और आज जो तरह-तरह के रोग होते है, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांव यहीं तक

[श्री रामलाल राही]

उपेक्षित नहीं हैं, आपने गांवों में हस्पताल खोलने की बात कही है कि 5,7 किलोमीटर के मध्य किसी न किसी पद्धति की औषधि के उपचार की व्यवस्था कर दी है, लेकिन क्या आपने यह पता लगाया कि कितने गांव में आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कायम हैं, उनकी इमारतेंबनी हैं, वहां डाक्टर बैठता है?

इस देश में कम से कम 50 फीसदी ऐसे हस्पताल हैं जिनमें डाक्टर जाते हैं तो दवाएं नहीं हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not want any other Member to speak on your Resolution ? You complete now. Other Members want to speak on your important Resolution.

श्री राम लाल राही : मुझे तो बोलने दीजिये, मैंने तो अभी सुझाव दिये ही नहीं हैं । आज स्थिति यह है कि अगर गांव के किसी व्यक्ति को कोई रोग होने के कारण तत्काल दवाई की आवश्यकता हो, तो उसे वह नहीं मिल सकती ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You please conclude now. You have got a chance to reply also, at the end. I will give you one hour to reply as a special case. You please complete. You have been talking for the last one hour. Keep something for replying also.

श्री राम लाल राही : मुझे दस मिनट और दे दीजिए ।

अस्पतालों में डाक्टर और दवाएं नहीं है । सरकार ने अस्पतालों की इमारतें भी नहीं बनवाई है । घोषणा की जाती है कि अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक पद्धति की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है । उनमें 50 प्रतिशत ऐसे स्थान हैं, जहां न डाक्टर जाता है और न कोई इमारत है । कहीं कहीं कंपाउंडर पहुंच जाता है और उसके सहारे वह स्थान जीवित है । यह कहा जा सकता है कि यहा पर कोई अस्पताल खोला गया है, लेकिन वहां पर दवाई नहीं है । मेरा कहना है कि चिकित्सा और दवाओं के मामले में सरकार ने गांवों और शहरों में जो फर्क बना रखा है, उस फर्क को उसे दूर करना होगा । अगर वह उसे दूर नहीं करेगी तो आवाज आ गई है कि चुनाव होने वाले हैं । जनता की आंखों के सामने सरकार के पिछले 37 सालों के शासन की तस्वीर नाच रही है । उसके इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा संचार साधनों की जो व्यवस्था की गई है, वह गांवों के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है ? सरकार ने पांच और सात किलोमीटर के बीच में सब पोस्ट आफिस खोला है, लेकिन उनसे क्या फायदा है ? क्या यह सही है कि ये पोस्ट आफिस इसलिए खोले जा रहे हैं कि जो लोग सत्तारूढ़ दल में काम करते हैं, उनको एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाए और उनके लिए महावार आमदनी की व्यवस्था की जाए ? अगर सरकार इनमें से दस सब पोस्ट आफिसिज की जांच करें, तो उसको मालूम होगा कि वह उनपर जितना रुपया खर्च करती है, उतनी चिट्ठियां साल भर में नहीं जाती हैं । तो क्या सरकार इन सब पोस्ट आफिसिज को किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं खोलती हैं ? क्या वह यह विचार नहीं करती कि इनसे कितने फीसदी जनता को लाभ होगा ? मेरा कहना है कि सरकार की नीति सही हो सकती है, लेकिन नीयत सही नहीं है ।

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : नीयत अभी सही है। क्रियान्वयन में थोड़ी भूल हो सकती है।

श्री राम लाल राही : अगर सरकार गांवों के इन सब पोस्ट आफिसिज में अल्प-बचत की व्यवस्था करा देती, तो जो गरीब खेतिहर मजदूर हफ्ते में दस, पंद्रह, पच्चीस या तीस रुपए कमाता है, वह उसमें से पांच रुपए बचा कर जमा करा देता। इससे जहां अल्प-बचत को बढ़ावा मिलता, वहीं गांव का गरीब खेतिहर मजदूर कोई आवश्यकता पड़ने पर या दैवी विपत्ति में उसी से अपना काम चला लेता, सरकारी और सहकारी बैंकों और महाजनों का वह ऋणी न होता। दो चार बीघा जमीन जोतने वाले किसान की जमीन नीलाम होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जितनी जमीन सीलिंग की निकाल कर गांव सभा की जमीन बांटने का ढोंग रचा है, उससे कहीं ज्यादा छोटे किसानों को सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कार्य दिया है उससे उन गरीबों की जमीनें नीलाम हुई हैं। उसने उनको ज्यादा भूमिहीन बना दिया है। इससे क्या लाभ हुआ गांव के लोगों का? इसमें आप को सुधार करना चाहिए।

अंतिम बात कहना चाहता हूं। अगर सरकार चाहती है कि गांव का विकास हो, गांव के लोगों के जीवन में सुधार हो, तो जहां शैक्षिक नीति में परिवर्तन होना चाहिए चारित्रिक सुधार होना चाहिए, नीति और रीति समान होनी चाहिए, वहीं प्रशासनिक ढांचे में भी परिवर्तन होना चाहिए। जब तक यह परिवर्तन नहीं होता, तब तक गांवों के विकास की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। **(व्यवधान)** हमारे यहां नगर पंचायत है। उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 गांव सभाएं हैं। इन नगर पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी हैं—लेखपाल, अमीन, कृषि अमीन, ग्राम सेवक, पंचायत सेक्रेटरी, स्वास्थ्य के दो कर्मचारी, पतरौल, कोआपरेटिव का कर्मचारी, इस तरह से कुल मिलाकर के करीब करीब 11-12 कर्मचारी गांव सभा में बैठते हैं। इनकी पोजीशन आप समझ लें। अगर हैल्थ वर्कर से बी० डी० ओ० आकर पूछता है कि क्या कोई मौतें हो गई हैं, कोइ बीमारी है तो वह कहेगा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। डाक्टर पूछे। मान लो डाक्टर पहुंच जाए तो...**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Rahi, when you move a resolution, you must hear the points of view of others. And you have got a chance to reply You will be given one hour to reply. You have now taken one hour already. Please complete it. Otherwise, I will call the next speaker.

श्री राम लाल राही : मेरा कहना यह है कि गांव का जो प्रशासनतंत्र हैं, उसमें केवल दो कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि आप उनको एक ही स्थान पर स्थायी कर दें, चाहे एक ही आदमी लगायें उसको सारा गांव सुपुर्द कर दें तो उससे कई लाभ होंगे। जितने गांव के काम हैं, वे कोई टैक्नीकल काम नहीं है। उस गांव के कर्मचारी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह गांव में रुके और उसको गैर हाजिरी करने के अवसर नहीं मिलेंगे। दूसरा गांव के प्रत्येक आदमी से उसका संबंध स्थापित हो जाएगा। खेत की मेड़-मेड़ से परिचय हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको गांव के प्रशासन को बदलना चाहिए। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के शासन ने जिला प्रशासन सुधार के लिए आयोग बनाया है। मैं कहना

[श्री रामलाल राही]

चाहता हूं कि आपको इसी तरह से आयोग बनाना चाहिए। अन्य बातें जो मैं कहना चाहता हूं वह मैं रिप्लाई के समय कहूंगा। धन्यवाद।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Mr. Deputy Speaker, Sir, when I heard the speech I could find that everything has been so much done in India that perhaps one does not like to see what has happened to this country and the rural India. Since 1980 if your government and the Prime Minister has taken up any programme seriously and tried to implement it with honesty giving so much emphasis and top priority, it is our 20-point economic programme.

It is this 20-Point economic programme and the major emphasis is anti-poverty programme, or removal of poverty, and improving the people below poverty line as we may like to call it. That is the most important programme that has been undertaken since 1980. The estimate of the people below poverty line varies according to the estimates of the Planning Commission and the evaluation studies, between 306 million to 280 million people, in our country For that we have got the Integrated Rural Development Progarmme, or IRDP as it is called. In the first four years of the Sixth Plan nearly 1.25 million people have been brought above the poverty line, as against the target of 15 million which will be soon reached at the end of March 1985.

Now, the total investment in the Sixth Plan is about Rs 3,400 crores under this IRDP and the number of families to be helped will be 15 million. In the Sixth Plan the programme was for the poorest of the poor. In every block 600 families should be identified or selected and the necessary help should be given to them so that they rise above poverty line, and accordingly about 5 million beneficiaries will be benefited at the end of this period.

Now, the Government wants to further accelerate this programme In the Seventh Plan a more courageous and ambitious programme is going to be undertaken by the Prime Minister and our Government. They want to raise the outlay per block from Rs.35 lakhs to Rs.1 crore. And then the beneficiaries will increase from 600 families to 5,000 families, and at the end of the Plan 25 million families will be benefited.

The subsidies that we give under the IRDP scheme vary from 25 to 80 percent. Even poor Harijans, backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes also get more subsidy, Some times They get even up to 100 per cent subsidy. As the hon Minister, Mr. Sethi is sitting here, I would like to draw his attention to the experience we have about the subsidies which are being given to help the poor people in the countryside. I want to place a sugggestion before the hon. Minister and the Planning Commission, with the utmost zeal and desire that they should see that the subsidy that is given reaches the people concerned, so that they rise above the poverty line. The subsidy has become a matter of corruption I have gone to various villages and I have seen what has happened to this subsidy. I hope some study has been made about the subsidy that is given. In some States the implementation has been ineffective. All the anti-poverty programmes and even those that are implemented through the banks are not properly implemented. The BDO's and other officers at the block level are not effective and it has been established that 40 per cent of the assistance given to the beneficiaries is taken away—I should not mention the names—by the *babus* I have seen it being mentioned in newspapers that 40 per cent of the subsidy is lost The Central Government is silent on this. Therefore, I have a suggestion—I venture to give it as Mr. Sethi is in charge of Planning—about the subsidy that is being given. In the Sixth Plan Rs 4,000 crores is the subsidy, if we take the subsidies given for fertilizers, under the IRDP schemes. May I suggest to the hon. Minister that instead of this subsidy which is creating a kind of black-money and certain people are creating a corrupting influence in the countryside, why not the poor people get

loan assistance free of interest ? I have talked to many poor people. They say that they shall be grateful to the Government of India and Shrimati Indira Gandhi if they really get this interest free loan.

MR. DEPUTY-SPEAKER : How do you say that even then this 40 per cent will not be taken away by these babus ?

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I fully agree with you. If you make it interest free, at least they will be saved of interest on that 40 per cent which they do not get, and to a certain extent this sort of fleecing will be minimized.

I am very happy to note that the Government of India has made the maximum effort to see that the poor people get all the benefits. If the per capita-investment under IRDP is taken, in 1981-82 it was Rs.1642 and in 1983-84 it was Rs.3154. In the Seventh Plan, they have given top priority to the IRDP. Once I was reading the views of one of the most noted economists of the country about these programmes and subsidy and he wrote :

> "There are enough funds with the Government of India to look after the poor people in the countryside and enough funds are being released, but powerful interests have emerged during all these years of planning, who did not allow the benefits to reach the poor."

Therefore, before we draw the Seventh Five Year Plan, we have to make an evaluation of all these programmes in order to see that the benefits should not be taken away by the middle-men. In Orissa about 26 BDOs and 26 bank officers were suspended From this you can judge to what extent this malpractice has gone. Supposing a cow is given, the cow is not there at all. So, in view of the experience that we have gained, we have to see that these difficulties and shortcomings which we have come across, are overcome during the Seventh Plan.

About the National Rural Employment Programme, this is one of the very good programmes that we have taken up for generating employment in the countryside. But on fact I want to bring to the notice of the hon. Minister. I was looking to the evaluation study. In 1980-81 this NREP generated 436 million mandays. It had declined to 354.52 million mandays in 1981-82. There was further decline to 350 million mandays in 1982-83 and in 1983-84 the figure is 300 million mandays So, I hope the hon. Minister while replying will tell us why this decline in generation of employment is there so far as our National Rural Employment Programme is concerned, though we are giving top-most priority to it. While touring my area, I found that one reason may be that sometimes the State Governments want to take all the advantages from the Centre but they want to show that this is their programme and not the Central Government's programme. I think some State Governments took it seriously when the Prime Minister said somewhere that the Central Government is releasing crores and crores of rupees for the upliftment of the poor but some State Governments, by giving a different name to it, say that this is their programme, I hope some State Governments take pride in that though the money is released by the Central Government. Therefore, the reason for the decline in the generation of employment may be because the State Governments have to pay some matching grant. Sometimes whatever grant is given by the Central Government, it is so calculated, the bureaucracy has developed a mechanism in such a manner, that it will look as if the State Government has given its matching Contribution of 50 per cent and the Central Government has given 50 per cent. The accounts are prepared in such a way that it appears as if the State Government has given its matching contribution Therefore, it may be because of this that there is declining trend in the generation of rural employment.

MR DEPUTY SPEAKER : You must cite some examples also to this effect.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I will write it down to the hon. Minister. I will send it in writing.

MR. DEPUTY SPEAKER : Of course confidentialy.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : The third important programme which the Prime Minister has announced and which the Government has taken up is the Rural Landless Employment Guarantee Programme. This is the most important programme and the Central Government is giving hundred per cent assistance to this programme. When I look at the implementation part of this programme, I find that there are number of shortcomings in this programme which should be overcome if the programme is to be made foolproof.

Another very important programe for the upliftment of the poor people is the Self Employment Scheme for the Educated Unemployed This Scheme is picking up very nicely. I have seen in my area how people are getting benefit under this Scheme and how it is helping them

Lastly, Sir, it was said that because of the tempo of development that is taking place, the stability of the villages is being disturbed and unless the programmes are fully and effectively implemented, there will be drift of the rural people towards the towns, Therefore, what we have to seriously think today is that after investing thousands and thousands crores of rupees for uplifting the poor people in the country-side, we should see that they are settled and get their livelihood. I was calculating from 1980 to 1984 and found that more and more people are drifting from the rural areas to the cities. What is happening today is that there is destabilisation in the villages and there are going to be urban disturbances I was telling yesterday that what we see in Punjab today is because of the urban frustration also. After the development in Punjab, the result that we see today is a kind of frustration among the youth, So, we have to see how this urban disturbance can be removed.

Now, I just cite one instance. When the banks were nationalised, Mr Sethi was incharge of Finance. I am grateful to him that the first branch of the nationalised banks was opened in one of the remotest places in my area, that is, Daspalla where thousands of people wanted to know what is a nationalised bank. That was the scene when Mr. Sethi went to inaugurate that branch. Today we find how the economists have analysed that the rural people are paying the high wage cost of the banking institutions. The banking industry is casting an additional burden of 4.5 per cent on the farmers, because of the payment of higher wages to the employees of the nationalised banks. Similarly, if you take the public sector enterprises, the rural farming community is paying 6.5 per cent, which is the additional burden on account of the wages paid to the public sector employees and these public sector units have aggregate loss of about Rs.200 crores in spite of the price increase allowed on the products of these enterprises. This loss is passed on to the rural farmers.

Since we are pumping more and more money into the rural side, a high-level committee should go into the problem, because this conflict is bound to increase in the countryside Therefore, the best way to safeguard the utilisation of the money that we are giving to the countryside is to involve the voluntary agencies in the implementation of the IRDP and all the anti-poverty programmes. As the Prime Minister has also suggested, all the voluntary agencies should be involved in these programmes I hope the Government of India is having some programme in this direction.

Coming to irrigation and electricity, of course we cannot discuss all of them because the scope of the resolution is limited. But, so far as irrigation, generation of energy, construction of roads etc. are concerned, there is no doubt that we have made tremendous progress. We cannot say that nothing has happen-

ed. The progress is remarkable. The more we go ahead, the more will be the desire for further achievement. We have to meet them As our Prime Minister has declared, all the programmes that we have undertaken are to see that India prospers and a new India is built up so that in a decade India becomes one of the front-rank members of the comity of nations.

SHRI CHITTA BASU (Barsat) : I rise to support the Resolution, moved by my esteemed friend, Shri Rahi. I am grateful to Shri Rahi that he has considered it necessary to raise a very important issue for discussion in this House.

16.30 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

The essence of the Resolution is that certain changes and necessary improvements in the administrative pattern of rural development have to be brought, about. While accepting or agreeing with these views, I would say that unless we realise and understand the basic problem of the rural areas, it will not be possible to solve the problem at all. It is a fact that there is growing discontent in the countryside. Therefore, unless certain radical measures are taken, instead of the green revolution, of which you are very much proud of, certain other kind of revolution will take place in our country.

Now, look at the profile of the countryside. Unemployment among the rural population is increasing by leaps and bounds. I have get a figure which suggests that at the end of March 1977, these who got their names registered in the Employment Exchanges at the district level – I am not mentioning about the cities of other big towns– their number stood at 10.2 million. Now during these years this figure has risen and reached to 19.7 million by 1983 Therefore, you can will appreciate the magnitude of the rural unemploymeat in our country.

Sir, again we are to take note of the increasing alienation of the agriculturists from the land. More and mor people are being alienated from the land. I would only give you one figure to indicate the rate at which this alienation is taking place. The ratio of agricultural labourers to cultivators, which was roughly 43 : 57 in 1951, has increased to 45 :53.5 by 1971 That means generally speaking by 1971 the ratio between the agricultural labour and the cultivators have been almost fifty-fifty. That means fifty percent of the rural population comprise of agricultural workers or labourers today.

Now, if you think in terms of the agricultural workers in our country, I would only quote the figures given by two Rural Labour Inquiry Committee. The say the number of agricultural labourers stood at 310 lakhs in 1964-65 and it rose to 460 lakhs in 1974-75. By 1983, the number might have crossed 500 lakhs. Therefore, we have got about five crores of agricultural workers, living in the rural part of the country

Now, while on the one hand the poor and the marginal peasants are being alienated from the land, on the other hand the number of large farms is increasing. This ought not to have taken place at all because we have got the land ceiling laws, because we have got certain land reforms policies. But contrary to all these things, the number of large farms is increasing. Can you explain why is it so ? Large farms account for an area of 386 lakhs of hectares, rather 28 9 per cent of the total cultivated area in 1961-62 Now, the number of large farms has increased and they cover about 500 lakhs of hectares i e. 35.8 per cent of the total area cultivated in 1970-71. That means there has been increase in the number of large farms and the total quantity of land under large farms has increased to a very great extent This means that the object of the land reforms has been completely defeated.

Now, if you take into account the success or achievements of land reform measures, I would only draw your atten-

[Shri Chitta Basu]

tion to the Report of the Agriculture Ministry, Government of India, which says that the total area of available surplus after the implementation of the ceiling laws would be only 46 lakh hectares, which constitutes only one per cent of the total cultivated land of our country.

Admitting this shortfall, rather admitting this defeat of the policy, the Approach Paper to the Seventh Five-Year Plan says :

> "Although substantial progress has been achieved in the implementation of the land reforms, a good deal of potential for re-distribution of surplus land stills needs to be realised."

There is a good deal of achievement. Your achievement, if I quantify, is that you have been able to distribute 70 to 90 thousand hactares of land Throughout this country you have quantified the total surplus land as only 46 lakh hactares of land which constitutes only 11 per cent of the total land cultivated in our country, and in your Approach Paper you do not admit this shortfall and deficiency and you merely express your satisfaction that you will try, during the coming five years of the Seventh Five Year Plan only making arrangements for taking over possession of 46 lakh hactares of land and distribute them. Can it really eliminate the real poverty in our country even if you succeed in distributing these 46 lakh hectares of land in our countryside ? My answer to this is ; No, it will not reduce the rural poverty because if you want to reduce the rural poverty, the main thing or the quintessence is the land reforms, and you have not understood the implications of the land reforms, the vital role it plays in a country like India — not only India, but in all developing countries.

Sir, I know you are an energetic student of history. Even a bourgeois economist will agree that in a developing country the key to the advanncement of the people lies entirely on the land reforms It is not only the question of India it is the question which is equally valid or which is equally relevant to all the developing countries of the world Unless the Government or the Planning Commission or the Ruling Party understands or realises the importance of this basic issue, I am afraid the problem of the rural poverty cannot be solved, cannot even be tinkered with ; you cannot even touch the fringe of the problem Therefore, while supporting the Resolution of Mr. Rahi, I would only request that instead of making so many speeches in diverse ways on policy decisions, the entire attention should be concentrated on land reforms. That is the key to the poverty eradication programme. But, Sir, unfortunately that has not been taken proper care of.

Coming to the other issues ..

MR. CHAIRMAN : Please conclude. There is very less time.

SHRI CHITTA BASU : Sir, I heard you very patiently. I want to answer you while you are there But now you are in the Chair.

MR. CHAIRMAN : But the time limit is only 10 minutes

SHRI CHITTA BASU : For the time being we assume that you are there, not in the Chair

MR. CHAIRMAN : You could have replied to me in 10 minutes. You conclude in 10 minutes

SHRI CHITTA BASU : Thank you, Sir. I will conclude

I am concluding only after replying to you.

You have said that the Government has taken measures for anti-poverty programmes and they are in operation. You have mentioned I R D P., National Rural Employment Programme, Rural

Landless Employment Guarantee Programme and other programmes.

Even the Government admits in the course of the reply to a question here that these programmes have also not been successful to the satisfaction of the people of the country. They also admit that there are certain problems in the implementation of them. The target has also not been fulfilled. It is necessary for the House to know what has been the success of these programmes. To what extent Government has been able to implement this poverty eradication programme. I suggest that the Government should appoint a Committee to re-evaluate the effect or consequence of this programme relating to the rural economy of our country particularly in the direction of poverty eradication.

Lastly, I would only mention about the artisans. As a matter of fact you will be unhappy to learn that the number of rural artisans are decreasing gradually. I have got figures at which I got from the National Sample Survey that was held in 1955. It says that the number of workers engaged in Household Industries in the country stood at 10.2 millions. It has come down to 6 35 millions, in 1971 census report. On the one hand the poor and marginal farmers are being gradually and increasingly alienated from the land. On the other hand the village rural artisans are also being alienated from their profession. Therfore, how can you expect that the rural unemployment will be solved and the problem of poverty will be reduced in the countryside ? Unless the Government takes up eradication of Poverty as a programme in the Seventh Five Year Plan, there cannot be any effective change. A new attitude is required, concentrate on the land reforms and bringing about or restore the household industries so that the people in a large number can get employment and poverty can be reduced.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao) : I join the other Members in congratulating the Mover of this Resolution for having brought it at a very appropriate time and focussed the attention of the House on this very important issue. Mahatma Gandhi used to say that India lives in the villages. In fact, as per estimate, 80% of the country's population lives in villages. It is not merely concentration of population in the villages. I am afraid, the concentration of poverty also is in the villages.

We have, undoubtedly, made tremendous progress over the last thirty and odd years. The benefits of this economic programme have mostly gone to the people in the town, in the urban areas and they have not gone to the corresponding extent to the rural population.

Now, my hon. colleague, Mr. Chitta Basu has rightly pointed out that in the rural areas, land, particularly the agricultural land is the basis of development. No doubt, land reforms are important but I don't think merely by giving a piece of land to a landless person, the problem of poverty of that person or the problems of rural poverty are solved. Equally important, if not more, is to see that the person who gets this land is able to like a living out of that and that agriculture becomes profitable. This is precisely what the schemes which have been brought in by this Government in the Sixth Five Year Plan. They have done it with great success. Now, what is the Integrated Rural Development Programme (IRDP) ? It is trying to give inputs to the farmers, marginal farmers of whom Shri Chitta Basu was speaking so that he can rise himseelf and his family above the poverty line.

Mr. Chitta Basu was speaking about the artisans whose number has increased and was expressing very serious misgivings about the future of artisans in the country. Then, it did not occur to him to make a reference to a very important programme that this Government had brought in, namely, TRYSEM. It aims precisely at this. It creates artisanal facilities in the rural areas and improvement by bringing semi-modern technology in the artisanal structure

[Shri Eduardo Faleiro]

which is in the rural areas. Now, what are the figures ? The Scheme TRYSEM is proposed to train at least 2 lakh rural youth every year some skill or technology. In 1979-80 and 1980-81 93,018 were trained and out of this 9,266 youths became self-employed. This is a very important substantial achievement. But apart from the achievement the direction to that programme, the perspective of the issue is also equally very important. Now, our previous speaker was mentioning what transpired in the House this morning when the Government said, "These programmes are satisfactory", they are not satisfactory enough. What are the reasons ? I should submit that reason no 1 is the lack of motivation at all levels. It is not enough if the hon. Planning Minister wants to push this programme ahead. It is not enough if the Government of India and its Minister want to push this programme ahead. It is necessary that everybody at the political level downwards and administrative level from top to bottom is motivated and made to understand the importance of these programmes and these anti-poverty measures. In the morning, we were all hearing one hon. Member blaming the poor bank managers in the rural areas. Some of us even went to the extent of saying that bank managers act *mala-fide* and withdraw these loans from those deserving cases. I have toured in my constituency, every single village panchayat in my constituency and my impression of these managers is not so much the case of malice when they withdraw the loan but it is a case of just ignorance. They are used partiularly to a set process in which loan must be given in a particular form and to the people who can reply them. The first thing they look into is, when a person goes for a loan, is this man able to repay the loan ? This is the question of not so much of malice but lack of knowledge of the purpose, intention and structure of this programme. Very often also, these bank managers do not know what is the rate of interest applicable. I go to a manager and he tells me, for this particular loan, the rate of interest is 20%. Another bank manager from the next village says, it is 10%. The third man says, no, the BIR rates will be applicable and it is 4%. These are the things. So, the question is not merely poor bank managers in the rural areas. Please tell me how much motivated will be the Directors of the Reserve Bank of India. Please have a talk and let our Members of Parliament have a talk with the Directors of the Reserve Bank of India They will be surprised to see that some of the Directors are not at all inclined for this programme. They find that these programmes are merely politically motivated.

Why go only to the Directors of the Reserve Bank of India ? Let us go to the Planning Commission which plans various programmes and schemes. Let us meet some of the senior officers of the Planning Commission and let us find out how motivated they are, how much belief and faith they have in these programmes. You will find some exceptional cases. You will find also other cases in which there is no belief in these programmes, there is no faith in these programmes. It is not out of malice ; it is just out of their ignorance. These are the people who have been trained in a particular school of thought ; they have been trained in a particular school of economics. They believe that it is the rich man who will bring in the result ; it is the big industry, what they call the mother industry, that will bring in the result. You have the mother industry ; you spend crores of rupees ; the ancillaries will come up and all the good things will happen as a consequence. So, it is just a question of motivation ; it is a question of education. These things must be brought about at all levels.

The kingpin in these programmes, the anti-poverty programme, is the Block Development Officer. One finds that the programmes do not succeed to the extent desirable though, I repeat, again and again, that they have succeeded to a very great extent. But I agree that they have not succeeded to the fullest extent. It is because there is no coordination at the basic unit of the block. We have

agricultural development officers ; we have labour officers ; we have education and health officers. All these people are connected with the 20 point programme. But the kingpin is the BDO. He is supposed to coordinate all these activities, all these programmes. The BDO because of his own junior rank—sometimes his scale of pay is lower than that of other officers—has no authority, has no statutory power, to direct other officers, nor he has the moral authority which a higher-rank officer has. The lack of coordination at the block level mainly is another hurdle in the greater progress and implementation of these programmes.

There are a lot of things one could say. The basic thing is a question of motivation and education. It is also a question of adequate staff and Personnel. We have at the village level the gram sewak. In my area, we call h m the gram sewak. This is the man who will meet the rural people, go to them and find out who are really the poorest people in the village so that they are helped. The gram sewak and the panchayat secretary are the officials whose scales of pay have remained stagnant for the last 20 years in most of the States. But the work that is being done at the village level and the block level is increasing tremendously. Every year, new programmes, are coming up ; every five years, there is a package of new programmes But the staff at the village and the block level is not increased.

I will end up by saying that the point raised in the resolution that has been moved by the hon. Member, Mr. Ram Lal Rahi, that education is important must be emphasized We are still going by the Lord Macaulay style of education which leads merely to white collar jobs which are not available. Education has to be, as Mahatma Gandhi wanted it, rural development oriented ; it must be oriented towards semi-modern technology. Education revolution is no less important than any other input for the rural development.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, मैं राही साहब के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह भारत की आत्मा का प्रस्ताव है। इससे पहले कि मैं कुछ इस पर कहूं मैं सेठी जी को मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा हुआ उन्होंने पिस्तौल को छोड़ कर कुदाल को हाथ में लिया है और गांधी जी का कुछ काम होगा। बहुत अच्छा काम होगा और देश का कल्याण होगा।

सभापति जी, आपने कहा है कि देश की गरीबी मिटी है, सत्य बात है। कुछ लोग तो गरीब से अमीर हुए हैं। मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, तो मालूम हुआ कि कांग्रेस के एम०पीज ने रोष प्रकट किया है। हाजी मस्तान जैसा व्यक्ति कुली से हाजी मस्तान बन गया। एक स्मगलर हिन्दुस्तान का एक चोटी का पूंजीपति हो गया। जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया। उस मीटिंग में एम० पीज ने कहा, वहां मिनिस्टर भी थे, कि उनको क्यो छोड़ दिया ? मैं आपकी बात की ताईद करता हूं कि बहुत तरक्की हुई है—एक कुली से करोड़ों का मालिक बन गया। ऐसे बहुत से लोगों ने तरक्की की है और आपने उनको बहुत तरक्की करवाई है। देश से कितनी गरीबी मिटी है कि एक कुली हाजी मस्तान और हाजी मस्तान ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं जो करोड़पति और अरबपति बन गए हैं।

सेठी साहब, मेरी दो-बार बातें लिख लो। हिन्दुस्तान में साढ़े चार लाख गांव हैं, 70-72 करोड़ की उनकी आबादी है और 70 करोड़ एकड़ जमीन है। इन साढ़े चार

[श्री मनीराम बागड़ी]

लाख गांवों में रहने वाले आदमियों को, नर और नारियों को, पशुओं की बात छोड़ दो, हालांकि अमरीका, रूस और यूरोप में पशुओं को भी उतना गन्दा पानी नहीं मिलता है, जितना हिन्दुस्तान में मिलता है। जो बाबा गांधी की सन्तान हैं, जो सही गांधीवाद के नेता हैं, जो सही गांधी के दारिस हैं—हम और आप तो नकली वारिस हैं—मैं उनको कहना चाहता हूं—इन साढ़े चार लाख लोगों को पीने का पानी दो। अगर आप ऐसा कर सके तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। एशियाड पर 1200 करोड़ रुपया खर्च करने से, यूरोप और अमरीका के बराबर शान बनाने से आपकी इज्जत नहीं बनेगी। वह तो गांधी की आत्मा को ठोकर मारना है, वह गांधी जो लंगोटी पहन कर जार्ज पंजुम से मिलने गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं—इन साढ़े चार लाख गांवों को पीने का शुद्ध पानी दो।

यह देश ऐसा है—जिसमें लड़ाई है बुरके की, पर्दे की है। भारत की जवान बहू-बेटियां सड़कों के ऊपर खुले-आम मैदान में पाखाना और जंगल जाती हैं, फरागत के लिये जाती हैं। कोई ऐसा बन्दोबस्त करो, जो आपकी बहन-बेटी इज्जत से, अदब से जरूरियाते-हाजत से फारिग हो सकें।

तीसरी बात -- आप के भारत में कम से कम 15 फीसदी लोग वे हैं जिनके घर नहीं हैं, जमीन नहीं है, झुग्गी नहीं है। जो खाना-बदोश हैं, जंगलों में घूमते हैं, दिल्ली या और जगहों में घूमते हैं। आप उनके बसाने का प्रबन्ध करो ताकि वे आवारा न रहें।

गांवों को आप फायदा नहीं पहुंचा सकते तो उजाड़िये मत। हलाकू और चंगेज ने गांवों पर इतना जबरदस्त हमला नहीं किया था जितना आपने किया है। गांधी जी किसानों के प्रतीक थे, उस गांधी के किसानों पर आपने हमला किया है। दिल्ली के पचास मील तक चारों तरफ किसानों की जमीनें छीनी गई हैं, डाका मारा गया है, चार आने, छः आने गज के हिसाब से उनकी जमीनों को लेकर हजारों रुपये गज तक बेचा गया है। मेरे ख्याल में बड़े से बड़ा डाकू भी इतना जबरदस्त डाका किसानों पर नहीं मार सकता था, जितना आपकी तरफ से मारा गया है। मैं कहना चाहता हूं अगर गांवों को नहीं बढ़ा सकते हो, तो दिल्ली को मत बढ़ाओ, कलकत्ता को मत बढ़ाओ, गांवों को सहूलियत नहीं दे सकते हो, तो कम से कम उनको उजाड़ों मत। आज कलकत्ता फैल रहा है, दिल्ली फैल रहा है, गांव उजड़ रहे हैं। आप गांवों को बसाने वाले नहीं हैं, उनकी भलाई करने वाले नहीं हैं, इसमें हम भी गुनहगार हैं क्योंकि यहां बात कुछ कहते हैं लेकिन बसना शहर में ही चाहते हैं, मकान शहर में ही बनाना चाहते हैं। आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। यहां पर अंग्रेज आया, बाहर से गौरी और गजनी आए लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लाल किले के पास किसानों की जमीन थी और आज दिल्ली के अन्दर फार्म हैं मंत्रियों के, बिरला के, टाटा के, डालमिया के और मोदी के लेकिन भारत के किसानों के पास जो पहले जमीन थी आज 50 मील के रकबे में एक इंच भूमि भी उनके पास नहीं है। ऐसी हालत आज यहां पर हो गई है।

पांचवी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेटी साहब आप कोई जादूगर तो हैं नहीं जो सब ठीक कर दोगे। या तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या इस सरकार को ट्रेनिंग दे रहे

हैं। आज कोई महकमा नहीं हैं, जिसको आपने छोड़ा हो। आपको कभी इस महकमे में भेज दिया और कभी उस महकमे में। जहां गलती देखेंगे, वहां उस महकमे को सुधारने के लिए आपको भेज देंगे। दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए भेज देते हैं कि इस महकमे को सुधारो। अब तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए जितना आप कर सको, करो। मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि आप शिक्षा सब को दो। बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े वकील हैं और दिल में दर्द भी है। 6,12,20 बच्चे स्कूल की इमारत के नीचे दब जाएं और मर जाएं, यह कैसी बात है। उन्हीं की रियासत के अन्दर ऐसा हुआ है। अगर कोई सभ्य देश होता, सभ्य सरकार होती या सभ्य समाज होता, तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये जो बच्चे हैं इनके तुम भी वारिश हो और हम भी वारिश हैं। इतने सारे बच्चे दब कर मर जाएं, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सभ्य कौम में नहीं हो सकती, किसी सभ्य समाज में नहीं हो सकती। मैंने 30 स्कूलों के लिए लिख कर दिया हुआ है कि इनकी इमारतें गिरने वाली हैं और वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी दिन इमारत गिर जाएगी, तो कहेंगे कि इमारत गिर गई और बच्चे मर गये, हम क्या करें।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करता हूं। मैं राही जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब वे प्रस्ताव लाए, तब तो आप हंस रहे थे।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं तो अब भी हंस रहा हूं, रो नहीं रहा हूं। देखिये आप विद्वान हैं और मैं अनपढ़ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि राही जी की भाषा का तरीका अपना हो और वे आपकी तरह इसको पेश न कर पाए हों लेकिन उन की जो भावना है, वह गांवों को बढ़ाने की है।

अब जहां तक आंकड़ों की बात है। सभापति महोदय, आप भी बहुत ज्यादा आंकड़े दे रहे थे। मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। एक लाला जी के पांच, छः बच्चे थे और एक दिन वे नदी पार करने के लिए गये। उन में जो सबसे छोटा बच्चा था, उसका कद एक फीट था, दूसरे का कद डेढ़ फीट, तीसरे का दो फीट और चौथे का कद ढाई फीट था और मियां, बीबी 6, 6 फीट के थे। नदी को उनको पार करना था। लाला जी ने हिसाब लगाया कि नदी तीन फीट गहरी है और सबका कद जोड़ कर औसत निकाल लिया कि पर-केपीटन कद सवा तीन फीट है और उन्होंने सोचा कि नदी पार कर जाएंगे। सब पानी में से निकले। अब बेचारे बच्चे तो सब डूब गये और वे दोनों निकल आए। तब सेठानी ने कहा कि यह कैसा गलत हिसाब लगाया कि ये सब मर गये। लाला जी ने फिर हिसाब लगाया और कहा कि 'लेखा जोखा यों. तो कुनबा डूबा क्यों' यह कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि पर कैपीटा का हिसाब आप बना देते हो लेकिन फिर भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं और दरिद्रता में लोग पड़े हुए हैं। पर कैपीटा पैसा आप के स्मगलरों के पास, भ्रष्ट लोगों, रिश्वतखोरों के पास चला जाता है, बेईमान लोगों के पास और बड़ी तन्ख्वाह पाने वालों के पास चला जाता है और गरीब के हिस्से कुछ नहीं आता है। आंकड़ों

[श्री मनीराम बागड़ी]

के हिसाब-किताब में वे सब रुपया खा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोहिया जी ने कहा था कि हरिजन की चव्वन्नी की चोरी पकड़ी जाएगी और जो करोड़पति टाटा और बाटा है, इसकी अरबों रुपये की चोरी नहीं पकड़ी जाएगी।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि राही जी को अपने प्रस्ताव को पेश करने का तरीका जरा कम ही मालूम होगा क्योंकि हजारों साल से वे एक दुःख अपने कलेजे में लिए बैठे हैं और कमलापति त्रिपाठी होते, तो श्लोक पढ़ कर सुना देते क्योंकि हजारों साल से उन्होंने यह काम किया है। हमें भाषा को नहीं देखना चाहिए बल्कि जो इस प्रस्ताव के पीछे भावना है, उसको देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जय बोलनी है, तो गांधी जी की, महात्मा गांधी की जय बोलो और श्रीमती इन्दिरा गांधी की नहीं। महात्मा गांधी के देश के लिए अगर आप कुछ कर सको, तो करो जिससे देश आगे बढ़े और इस देश के गरीब लोगों का कल्याण हो सके और गांवों को उजाड़ो नहीं, उनका विकास करने के लिए और ज्यादा पैसा उन पर खर्च करो। यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। पहले तो आपको पंजाब को देखने की तरफ लगा रखा था, अब आपके जिम्मे यह बात आ गई है। आप विद्वान हो। यह तो सरकार की बात है कि हाजी मस्तान छूटेगा, देश यूं ही लूटेगा और गरीब यूं ही फूटेगा।

MR. CHAIRMAN : The time allotted far this Resolution is 2 hours and now 2 hours is already over. Should I call the Minister ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : No, no. All parties should be given a change to speak.

SHRI RAM PYARE PANIKA : 2 hours is quite inadequate. Time may be extended.

MR. CHAIRMAN : How much time more do you want ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Minimum 2 hours.

MR. CHAIRMAN : I hope the House agrees that the time for this Resolution be extended by 2 hours.

SOME HON MEMBERS : Yes, yes.

MR CHAIRMAN : The time is extended by 2 hours. Now Shri Ram Pyare Panika.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, सम्मानीय राही जी जो प्रस्ताव लाए हैं, उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। जब हमें आजादी हासिल हुई तो देश के सामने कई विकट परिस्थितियां थीं जैसे कि देश को सुरक्षित रखना देश में एकता रखना और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। आपको मालूम होगा कि स्व० पण्डित नेहरू जी के नेतृत्व में सारी समस्याओं के निराकरण करने का काम लिया गया था। इस तरह, कई आर्थिक उत्थान के काम किए गए। इसी प्रकार पहली योजना में इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दिया दूसरी में एग्रीकल्चर पर दिया। इस तरह से हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हम अपनी आवश्यकतानुसार बदलते रहे।

राही जी ने कहा कि देश ने तरक्की नहीं की है, यह बात सही नहीं है। क्या यह बात सही नहीं है कि 1947 में हमारी औसत आयु 27 वर्ष थी और आज 52 वर्ष है जबकि देश में कई प्रकार की कठिनाइयां आई। पांच-छह लड़ाइयां हमने लड़ीं। सूखा, बाढ़, ओला और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी उत्तरोत्तर विकास की प्रगति बढ़ती गई। (व्यवधान) ... पासवान जी इस समय हंस रहे हैं। मैं इनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने तो योजना को रोल करके रख दिया था और विकास की गति आगे जाने की बजाय पीछे की ओर चली गई थी। औद्योगिक उत्पादन 1.4 प्रतिशत पीछे चला गया था। इसी प्रकार कृषि और जीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ा था। सन् 1980 में इनके आपसी लड़ाई-झगड़ों के कारण जब जनता का ध्यान हट गया तो उसने हमारी नेता श्रीमती गांधी में विश्वास प्रकट किया और हम दोबारा सत्ता में आए। सन् 80 में जो हमें जर्जरित अर्थव्यवस्था मिली थी, उसे ठीक किया और पटरी पर ला दिया। आज हम ऊंचा मस्तक करके कह सकते हैं कि 15 करोड़ टन गल्ले का उत्पादन हुआ। इन लोगों ने जो रोलिंग प्लान रख दिया था, उसे फिर से ठीक किया। इसका सारा श्रेय प्लानिंग कमीशन के लोगों को जाता है। हमारे देश की नेता जी को जाता है, इंदिरा गांधी जी को जाता है, इंदिरा गांधी को जाता है कि किस तरह से थोड़े टाइम में इन्होंने हमारी योजनाओं को रोल कर दिया था...

सभापति महोदय : पनिका साहब, आपका टाइम सिर्फ 10 मिनट है, इसलिए समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका : चूंकि ये लोग नकारात्मक बातें करते हैं, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। आप भी एग्री करेंगे कि जिस तरह की ये बातें करते हैं, मैं इनको ठीक कर रहा हूं। आखिर मंत्री महोदय भी कितने आदमियों का उत्तर देंगे। इसलिए हमारा भी कर्त्तव्य हो जाता है...

सभापति महोदय : आप इस तरफ मत देखिए।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं आपकी ही तरफ देख कर कहूंगा। हमारे विकास के मार्ग में रोडा बनने वाला दूसरा प्रमुख कारण सस्ती लोकप्रियता रही है। मुझे खुशी है कि हमारे लोक सभा सचिवालय ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। मैं इनका बड़ा आभारी हूं। सभापति महोदय जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, उन राज्यों में देखें, जैसे वेस्ट बंगाल है, आन्ध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, वहां ग्रामीण विकास के बहुत कम लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैं यह रिकार्ड की बात कह रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारे गांवों में देश की 85 प्रतिशत जनता रहती है। छठी पंच वर्षीय योजना के अंत तक हम 51 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने जिन गांवों को बिजली दी है, पम्पिंग सेटस को एनजाईज किया है, इरीगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया है, इसके अलावा कई दूसरे कार्यक्रम सब के सामने हैं। यह बात भी सही है कि जितने विकास की हम अपेक्षा रखते थे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये। उसका कारण यह था कि हमारे देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थीं। आप

[श्री राम प्यारे पनिका]

देखिए कि हमारे देश में पोलिटिकल स्थिति क्या है। विकास कार्यक्रमों के लिए और भी कई चीजों की अपेक्षा होती है, कई बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है। देश के पोलिटिकल ढांचे का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। हमारे गांधी जी के देश में आज कितनी पार्टियां हो गई हैं और हर रोज एक नई पार्टी बनती चली जा रही है। हमारे विरोधी दल वालों को भी देखना चाहिए कि इनस्टैबिलिटी का हमारे विकास कार्यों पर कितना गहरा असर पड़ता है।

इतना ही नहीं, हमारी पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत छः भिभिन्न प्रकार के एरियाज को आइडैन्टिफाइड किया गया था जैसे हिल एरिया, मरुस्थल एरिया, ट्राइबल एरिया, डाउन प्रोन एरिया आदि आदि। मान्यवर आपका उड़ीसा का एरिया भी उसमें आता है। उसके बाद उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए। लेकिन छठी पंच वर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में उन बातों का जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि उन इलाकों का विकास राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम रीजनल इम्बैलैंस को दूर कर सकें। इसमें उड़ीसा के कई जिले, उत्तर प्रदेश के कई जिले और स्वयं मेरी कांसटीटूऐंसी मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के कई इलाके कवर होते थे। लगभग हर राज्य में काफी बड़ा इलाका आता था जहां लिंक रोड़ बनाने की आवश्यकता थी, सड़कें बनाने की आवश्यकता थी, स्कूल कालेज खोलने की जरुरत थी। मेरी कांसटीटूऐंसी राबर्टसगंज भी वैसे ही इलाके में आती है।

मान्यवर, यदि आप तो शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड लोगों की संख्या देखें तो वह कुल आबादी का 50 प्रतिशत बनती है। मैं आपकी बात भी सुन रहा था कि जितने हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे बीस सूत्री कार्यक्रम एन० आर०ई०पी०, आई०आर०डी०पी० आदि, उसमें सुधार की तो जरूरत है लेकिन दूसरी यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक हम ने कई ऐसी जातियों को मान्यता ही नहीं दी है। जब हमारे मंत्री जी होम मिनिस्टर थे तो इन्होंने कई बार इसी हाउस मे कहा था कि जो छूटी हुई जातियां हैं, हम उनको भी शैड्यूल में शामिल करके उनका विकास करेंगे। लेकिन मैं योजना मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सारे देश के इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पीछे एक शिवरामन कमेटी बनी थी। उसमें किसी जिले के इंडस्ट्रियल बैकवर्ड नैस को आधार न मानकर ब्लाक स्तर को आधार माना गया था। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि दो साल होने के बावजूद अभी तक उसको मान्यता नहीं दी गई है। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी भी कहते थे कि हो जायगा, उसके बाद चव्हाण साहब भी कहते थे कि हो जाएगा अब आप आये है, मै आपसे भी कहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी शिवरामन कमेटी को मान्यता दें ताकि देश में समान रूप से विकास हो सके।

अभी हमारे उस तरफ के कई लोग जैसे पासवान जी और कुछ दूसरे साथी उछल रहे हैं। लेकिन यह बड़ी गंभीर बात है। आप सातवी योजना के ऐप्रोच पेपर के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए काफी करने जा रहे हैं। लेकिन इस पेपर के 23 पृष्ठ पर जो लिख दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये जो सोशल बैकवर्डनेस का क्राइटीरिया रहा है उसको

चेंज करके आर्थिक करने जा रहे हैं, यह मेरी राय में ठीक नहीं है। आपको अपने उत्तर में स्पष्ट करना चाहिए। आपकी मंशा नहीं है, यह मैं जानता हूं, लेकिन न जाने कैसे ब्यूरोक्रेटिक सैट अप ने इसको रख दिया है, जो एक खतरनाक चीज हो सकती है। इसलिये आप माननीय पासवान जी को लोगों को भ्रमित करने का मौका न दें। जब संविधान में अनुच्छेद 340, 341, 342 रखे गये बैकवर्ड के लिये ऐजूकेशनली और सोशली, क्राइटीरिया की बात है फिर आपने ऐप्रोच पेपर में बैकवर्ड को क्यों निकाल दिया। अनुच्छेद 341 था शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए। अनटचेबिलिटी उसका आधार हो गया। अभी भी यह व्याप्त है। आज राजनीतिक अनटचेबिलिटी हो गई है। अनुच्छेद 342 में रिमोटनैस आफ दी प्लेस। आपने कहां रिमोट एरियाज को सम्पन्न क्षेत्र के साथ जोड़ दिया ? तो चालाकी से ब्यूरोक्रेटिक सैट अप ने 13 वां पैरा एप्रोच पेपर में बना दिया। आप स्पष्ट बतायें कि ऐसा क्यों किया गया ? और कहें कि हमारी मंशा ऐसी नहीं है ताकि माननीय पासवान को रेडियो, अखबारों और मीटिंग में यह न कहना पड़े कि आधार गलत है। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार की कभी यह नीति नहीं रही है। जब आप दूसरी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट को संशोधित करने जा रहे हैं तो मंत्री जी को सरकार की नीति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि पासवान जी को लोगों को भ्रमित करने का मौका न मिले।

इसी तरह से जो सिंचाई सुविधायें आपने दी, हमने दौरा करके देखा है कि नहरों की सफाई ठीक नहीं है, ट्यूब वैलों को बिजली समय पर नहीं मिलती है, गूलें भी ठीक नहीं हैं। यह छोटी-छोटी बातें हैं अगर इन को दूर किया जाय तो काफी सुधार हो सकता है। शिक्षा के बारे में माननीय राही और माननीय फैलीरो ने जो कहा ठीक है। अभी हम साउथ कोरिया गये थे वहां हमने देखा कि 10 साल में शिक्षा पर उन्होंने बहुत कुछ किया है। जब तक मेन पावर को आप ठीक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। कागज पर 27 प्रतिशत ऐजूकेशन कही है, लेकिन असल में 10, 15 प्रतिशत ही है। इसलिये देश में मैन पावर को ट्रेन करके समयानुसार उनको खड़ा करना है। इसके लिये जरूरी नहीं है कि शहरों में ही स्कूल हों। आज जरूरत है कि उनको देहातों में ले जाया जाय ! जो भी देहात का लड़का शहर में आता है वह फिर देहात मे वापस नहीं जाना चाहता। ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी शहरोन्मुखी हो गई है। न डाक्टर, न बी० डी० ओ० न इंजीनियर, कोई भी देहात में नहीं जाता है। इसके लिये जरूरी है कि प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों को और निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को गावोंन्मुखी ट्रेनिंग देनी चाहिये।

मैं अभी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा था, तो मैंने जानबूझ कर ब्लाक सिटिंग में पूछा कि जो अधिकारी 20 सूत्री कार्यक्रम को गिना देगा उसको हम इनाम देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बात को सुन कर बी० डी० ओ० सहम गया, वह भी नहीं जानता था। तो जो डैवलपमेंट के काम में लगे हुए अधिकारी हैं उनको हमारी नेता के कार्यक्रम को जानना चाहिए। अगर कोई एम० पी० नहीं जानता है तो उसको एम० पी० होने का अधिकार नहीं है। जो हमारे देश की नेता के 20 सूत्री कार्यक्रम को न जाने उसको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

[श्री राम प्यारे पनिका]

नहीं है। इन बंद शब्दों के साथ मेरा कहना है कि हमारे देश में बहुत काम हुआ है, और हो सकता है।

मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे 5 बजे जाना है, लेकिन चूंकि समय देर से मिला इसलिए मेरा कार्यक्रम नष्ट हो गया और अपनी बात भी खुल कर न कह सका। लेकिन कभी-कभी जब हम रिक्वैस्ट करें तो समय देना चाहिए। सभापति महोदय, मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूं। मैंने 5 बरस में पहली बार रिक्वैस्ट किया मुझे 5 बजे जाना है, एप्वाइन्टमैंट है, पहले समय दे देना। आपसे भी मैंने रिक्वैस्ट किया था लेकिन आपने दूसरे सदस्य को बुला लिया। अब मैं आपका आदेश मानता हूं और बैठता हूं। धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, पनिका जी ने एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया और वह है सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो यह प्रारूप जोड़ा गया है अनुसूचित जाति और जन-जातियों के रिजर्वेशन को समाप्त करने की दिशा में, जो कि पहला कदम है, मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं खींचूंगा जो कि यहां हो चुकी हैं।

मैं एक दो बातो की ओर मुख्य रूप से सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा कि सर-कार कम-से-कम यह मन तो बना ले कि मुझे कोई एक काम करना है। अभी जो आंकड़े दिये गये हैं और हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनसे हमको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आजादी के 37 साल के बाद हमारा यह देश या हम या गांव के लोग विकास की प्रगति पर हैं।

गांव में जो छोटी आवश्यकताएं हैं, हमारे अधिकांश साथी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उन को भी पता है, हमने आज तक संसार में कहीं ऐसा मुल्क नहीं देखा कि वहां आदमी को पीने के लिए अच्छा पानी न मिले। लंदन में मिलियन टन्स, लोखों टन दूध फेंक दिया जाता है, इसलिये कि दूध का एक्सट्रा उत्पादन वहां होता है। अमेरिका के किसानों को मुआवजा दिया जाता है कि तुम अतिरिक्त गेहूं या चावल पैदा न करो। लेकिन हमारा एक देश ऐसा है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई रहना नहीं चाहता है, सब विदेश भागना चाहते हैं।

मैंने एक दिन कहा था हिन्दुस्तान में अंग्रेज का राज्य था और आजादी मिली तो एक भी अंग्रेज यहां नहीं रुका, लेकिन अगर कहीं हिन्दुस्तान का राज्य इंग्लैंड में होता तो ऐसी स्थिति में एक भी हिन्दुस्तानी वहां से उठकर न आता, सब कहते कि घर यहीं बना लेंगे। इसलिये कि हमारे यहां आदमी की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हैं।

रोटी, कपड़ा और मकान का हम नारा लगाते हैं लेकिन आज भारत में 5 लाख 76 हजार 916 गांव हैं, आधे गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 37 साल की आजादी के बाद भी हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है?

जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के विलेज हैं, वहां पर इंसान उस जगह पानी पीते हैं जहां जानवर पानी पीते हैं। नतीजा यह होता है कि सारे जर्म्स इन्सान के भीतर चले जाते हैं और कीड़ा

शरीर को फाड़कर निकल जाता है। मंत्री जी के प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स में यह होता है।

सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम का हवाला दिया है। मैं जानता हूं कि इस 20-सूत्री कार्यक्रम को कोई जानता नहीं है। हम भी इसलिये जानते हैं कि इसको पढ़कर सरकार को समझाना होता है। जिस विभाग का यह कार्यक्रम है उस विभाग के मंत्री के अलावा कोई दूसरा मंत्री, एम० पी० या एम० एल० ए० इसको जानता नहीं हैं, गांव की बात तो दूर रही। इसलिए इस 20-सूत्री और 25-सूत्री को छोड़िये। समय आपके पास नहीं है, यह सही बात है। आपको इस विभाग का भार उस समय सौंपा गया है जब कि समय नहीं है, लेकिन आप कम-से-कम एक योजना तो अवश्य बना लें कि हम दो साल में प्रत्येक गांव में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा एचीवमेंट और कुछ नहीं होगा। इसमें ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आजादी के 37 साल के बाद भी हमने पीने के पानी की व्यवस्था नही की है।

17.25 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the chair*]

सभापति महोदया, गरीबी की रेखा की कोई पहचान नहीं है। गरीबी का अर्थ क्या है ? विदेशों में जिसके पास कार रेफ्रीजरेटर कपड़े धोने की मशीन और मकान है, वह भी गरीब माना जाता है। हमारे यहां प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग यह वर्ग-लाने वाली बात कहते हैं कि गरीबी विदेशों में भी है और हिन्दुस्तान में भी है। मै दो महीने बाहर रहकर आया हूं। हमारे यहां गरीबी का क्या अर्थ है ? प्लानिंग कमीशन कहता है कि गरीबी का अर्थ है 75 पैसे प्रति-दिन। हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं—प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 48 परसेन्ट।

इस देश में जितने बढ़िया और खूबसूरत फाइव-स्टार होटल हैं, वैसे संसार के किसी भी देश में नहीं होंगे। हिन्दुस्तान में एक तरफ अमीरी का कैलाश है और दूसरी तरफ गरीबी का पाताल है। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है, जिसमें कुछ राज्यों में लोग बाढ़ के कारण मर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में लोग सूखे से मर रहे हैं। हम इन दोनों में लिंक कायम नहीं कर पाए हैं, कोई नेशनल ग्रिड नहीं बना पाए हैं। बाढ़ और सूखे से हमारा जितना नुकसान होता है, उसकी आधी रकम से हमारी वह योजना तैयार हो जाती।

मंत्री महोदय अपने जवाब में बताएं कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारे पास साधन कितने हैं। पीने का पानी तो एक न्यूनतम आवश्यकता है। उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इच्छा-शक्ति की कमी है, पैसा उस में बाधक नहीं है।

आजादी के 37 सालों के बाद हमें बंधुआ मजदूर, बांडिड लेबर, के बारे में कानून बनाने पड़ते हैं। संसार भर में स्लेवरी खत्म हो गई है। काले लोगों को गोरे लोगों पर इस लिए गुस्सा है कि उनके द्वारा उन्हें गुलाम बना कर रखा गया था। आज हमें हिन्दुस्तान के गांवों और शहरों में गुलामी का जीता-जागता चित्र देखने को मिलता है। गांव के लड़के या नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। उसके जीवन में कभी सूर्यो-

[श्री राम विलास पासवान]

दय नहीं देखा है। उसका पूरा जीवन एक सूर्यास्त है, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। यह है हमारे देश का नक्शा।

पूरी दुनिया में जितने पशु हैं, उनमें से आधे पशु हमारे देश में हैं। लेकिन आज तक हम पशु बीमे की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। आज ही कृषि मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह, ने कहा कि जिसके पास अच्छी गाय है, वह जा कर बीमा करा ले। यह कोई जवाब है? अगर सरकार गांवों को ऊपर उठाना चाहती है, तो उसे पशुओं और फसल के बीमे की योजना बनानी पड़ेगी।

बाढ़ और सूखे से प्रति-वर्ष 800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, अर्थात आजादी के बाद 30,000 करोड़ रु० का नुकसान हो चुका है। इस रकम से सरकार बड़ी से बड़ी योजना बना सकती थी। योजना मंत्री को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में रूरल डेवलपमेंट का लक्ष्य रखना पड़ेगा। मेरा चार्ज है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण यह देश कंगाल हो गया है। मेरे पूछने पर सरकार ने बताया कि गांवों में 70 परसेंट विद्युतीकरण हो गया है।

सभापति महोदय : अब आध घंटे का डिसकशन होगा। माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

———

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Steps to increase Production of Groundnut

श्री राम लाल राही (मिसरिख): सभापति महोदया, सौभाग्य से आप सभापति की चेयर पर बैठी हैं। हमारे ही जनपद से आप इस सभा में संसद-सदस्य चुन कर आई हैं। हमारे जनपद की समस्याओं से, वहां के किसानों की समस्याओं से और वहां की पैदावार से आप भली-भांति परिचित हैं। मैंने ग्राउंडनट के बारे में प्रश्न पूछा था। मेरे क्षेत्र में और मेरी जनपद के कई पड़ौसी जनपदों में मूंगफली की खेती की जाती है। आप जानती हैं कि सीतापुर उत्तर भारत की मूंगफली की प्रमुख मंडी रही है। इसके अलावा फरुखाबाद साइड में भी कई जिले ऐसे हैं जिनमें मूंगफली अच्छी पैदा होती है। मुझे याद है कि जहां 1972-73 में सीतापुर के बाजार में प्रति दिन 70-80 हजार बोरी मूंगफली आती थी वहीं अब यह घट कर 7-8 हजार बोरी प्रति दिन रह गया है।

मैंने प्रश्न पूछा था—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। वर्ष 1980 से 1983 तक की अवधि के दौरान वर्ष वार और राज्यवार मूंगफली की प्रति हैक्टर पैदावार कितनी थी? यदि हां तो सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं।

(क) का उत्तर दिया गया है कि देश में मूंगफली के उत्पादन में उन वर्षों में जिन मौसम प्रतिकूल था, को छोड़ कर काफी बृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कमी होने के कारण हाल ही के वर्षों में उत्पादन में कमी आई है परन्तु 1983-84 में उत्पादकता गत वर्ष से अधिक रही है। अब उसके आंकड़े आपने दिए हैं—